

मौलिक मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए, भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। बाद में यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्ष 1976 में संविधान में ^{42वां} संशोधन करते हुए संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। इसे संविधान के ^{भाग} 'चतुर्थ अ' के रूप में जोड़ा गया एवं अनुच्छेद - 51 (ए) के रूप में जोड़ा गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 10 मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार हैं:-

- (i) संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान - भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
- (ii) राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन - भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे।
- (iii) भारत की समृद्धता, एकता और अखण्डता की रक्षा - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की समृद्धता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाये रखे।

(iv) देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(v) भारत के लोगों में समरसता और आतृत्व की भावना का विकास - भारत के सभी लोगों में मजबूत संबंध और समान आतृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रजाति या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी क्रियाओं का भाग करे, जो हिंसा की मर्यादा के विरुद्ध हो।

(vi) समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा - हमारी समन्वित संस्कृति के गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और संरक्षण करे।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन, मत्स्य, नदी और वन्यजीव भी हैं की रक्षा और उनका संरक्षण करे तथा प्राणी-मानव के प्रति दया भाव रखे।

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास - प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुचारु की भावना का विकास करे।

(ix) सापेक्षिक सम्पत्ति की सुलझा व हिंसा से दूर रहना - प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह सापेक्षिक सम्पत्ति को सुलझा रखे तथा हिंसा से दूर रहे।

(x) व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रभास-
प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी
क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें,
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयानों और
उपलक्षियों की ऊँचाईयों को दू लफ़ें।

(xi) वर्ष 2002 में, 86वाँ संवैधानिक संशोधन करके
अनुच्छेद - 51 (क) को संशोधित करते हुए 11वाँ
मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यह मूल कर्तव्य -
"माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा
कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों की
शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रदान करें।"

आलोचना - मूल कर्तव्य के संबंध में यह
आलोचना की जा सकती है :-

(i) कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था नहीं - भारतीय
संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर
दण्ड का प्रावधान नहीं है।

(ii) भाषा की अस्पष्टता - आलोचकों के अनुसार, संविधान
में वर्णित कई मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है।
उदाहरणार्थ - सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में

अक्षरों के प्रसारण, वैज्ञानिक शिक्षण, मानववाद और समाज के विकास

(iii) आभिव्यक्ति आदिवासी - आलोचकों के अनुसार,
अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर आभिव्यक्ति
आदिवासी और कोरे आदिवासी हैं।

(iv) शासन के आभाचार की आंशिकता - आलोचकों के अनुसार
मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में, जिस शब्दावली को
अपनाया गया है, उसकी आड़ में शासन, जनता पर
आभाचार कर सकती है।